IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

नई शिक्षा नीति के नियम और अवसंरचना की कमी

अवनीश चंद्र सोनकर

असिस्टेंट प्रोफेसर

शिक्षाशास्त्र विभाग श्री बजरंग स्नातकोत्तर महाविद्यालय दादर आश्रम सिकंदरपुर बलिया

सार - यह शोध आलेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख नियमों एवं उसके क्रियान्वयन में आने वाली अवसंरचनात्मक चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, कौशल-आधारित, बहुविषयक तथा तकनीक-संपन्न बनाना है। इसके अंतर्गत 5+3+3+4 शिक्षा संरचना, मातृभाषा में शिक्षण, डिजिटल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सतत मूल्यांकन जैसी व्यवस्थाओं को लागू करने पर बल दिया गया है। हालाँकि, नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं की कमी एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आती है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, इंटरनेट, स्मार्ट कक्षाओं तथा प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव नीति के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। यह आलेख नई शिक्षा नीति के प्रावधानों और वर्तमान शैक्षिक अवसंरचना की वास्तविक स्थिति के मध्य अंतर को रेखांकित करता है। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि शिक्षा बजट में वृद्धि, डिजिटल संसाधनों का विस्तार, शिक्षक प्रशिक्षण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष निवेश के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान संभव है। यदि नीति के साथ-साथ आवश्यक अवसंरचना का विकास सुनिश्चित किया जाए, तो नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक गुणवत्तापूर्ण, व्यावहारिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

मुख्य शब्द - नई शिक्षा नीति, अवसंरचना।

प्रस्तावना- भारत की शिक्षा व्यवस्था किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास की आधारशिला मानी जाती है। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिक जागरूकता, नैतिक मूल्यों के विकास तथा राष्ट्रीय प्रगति का प्रमुख साधन भी है। बदलते वैश्विक परिवेश, विज्ञान एवं तकनीकी के तीव्र विकास, डिजिटल क्रांति तथा रोजगार की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। यह नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला, बहुविषयक, कौशल-आधारित तथा विद्यार्थीकेंद्रित बनाना है, जिससे विद्यार्थी केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रहकर व्यावहारिक और रोजगारपरक दक्षताओं का भी विकास कर सकें।

नई शिक्षा नीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। पारंपरिक 10+2 शिक्षा प्रणाली के स्थान पर 5+3+3+4 संरचना को अपनाया गया है, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को भी औपचारिक शिक्षा से जोड़ा गया है। नीति में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा देने पर विशेष बल दिया गया है, ताकि विद्यार्थी विषयों को सरलता से समझ सकें और उनकी सीखने की क्षमता में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षण, वर्चुअल लैब, कौशल

विकास, व्यावसायिक शिक्षा तथा बहुविषयक अध्ययन जैसी व्यवस्थाओं को भी बढ़ावा दिया गया है। नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, नवाचार तथा समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना है, जिससे वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बन सकें।

हालाँकि, नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के समक्ष अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जिनमें अवसंरचना की कमी सबसे प्रमुख समस्या है। देश के अनेक विद्यालयों और महाविद्यालयों में पर्याप्त भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर तथा इंटरनेट जैसी आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी अधिक चिंताजनक है, जहाँ कई विद्यालयों में बिजली, स्वच्छ पेयजल तथा शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव देखा जाता है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है, किंतु इंटरनेट और तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थी इससे वंचित रह जाते हैं।

इसके अतिरिक्त प्रशिक्षित एवं तकनीकी दक्ष शिक्षकों की कमी भी नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है। नई शिक्षण पद्धतियों तथा डिजिटल माध्यमों के उपयोग के लिए शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है, किंतु अधिकांश शिक्षण संस्थानों में इस दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण भी कई विद्यालय और महाविद्यालय आधुनिक सुविधाओं का विकास नहीं कर पा रहे हैं।

अतः यह स्पष्ट है कि नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, किंतु इसकी सफलता के लिए मजबूत शैक्षिक अवसंरचना का विकास अत्यंत आवश्यक है। यदि सरकार, शिक्षण संस्थान तथा समाज मिलकर आधारभूत सुविधाओं के विकास, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता तथा शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दें, तो नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और भारत एक ज्ञान-आधारित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विकसित हो सकेगा।

1. नई शिक्षा नीति : उद्देश्य एवं स्वरूप- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, समावेशी तथा कौशल-आधारित बनाना है। इस नीति में विद्यार्थियों के समग्र विकास पर विशेष बल दिया गया है। नई शिक्षा नीति केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यावहारिक शिक्षा, रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन तथा रोजगारपरक कौशलों को भी महत्व देती है। इसके अंतर्गत 5+3+3+4 शिक्षा संरचना, मातृभाषा में शिक्षण, डिजिटल शिक्षा तथा बहुविषयक अध्ययन जैसी व्यवस्थाओं को लागू किया गया है। यह नीति विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है।

2. शैक्षिक अवसंरचना का महत्व- किसी भी शिक्षा नीति की सफलता के लिए मजबूत शैक्षिक अवसंरचना अत्यंत आवश्यक होती है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में पर्याप्त भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर तथा इंटरनेट जैसी सुविधाएँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अनिवार्य हैं। नई शिक्षा नीति में डिजिटल एवं तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, इसलिए आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि शैक्षिक संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव रहेगा, तो नीति के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त करना कठिन होगा।

3. डिजिटल शिक्षा और तकनीकी चुनौतियाँ- नई शिक्षा नीति में डिजिटल शिक्षण, ऑनलाइन कक्षाओं तथा वर्चुअल लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल शिक्षा की आवश्यकता और अधिक स्पष्ट हुई। हालांकि भारत के अनेक ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट, कंप्यूटर तथा बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन एवं डिजिटल उपकरणों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। इस कारण सभी विद्यार्थियों को समान रूप से डिजिटल शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

4. शिक्षक प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता सुधार- नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित एवं दक्ष शिक्षकों की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, तकनीकी उपकरणों तथा बहुविषयक शिक्षण प्रणाली को अपनाने के लिए शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। वर्तमान समय में अनेक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी देखी जाती है। कई शिक्षक डिजिटल शिक्षण तकनीकों से पूर्णतः परिचित नहीं हैं, जिसके कारण नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को लागू करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में नई शिक्षा नीति की चुनौतियाँ- ग्रामीण भारत में नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है। यहाँ अनेक विद्यालयों में पर्याप्त कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा डिजिटल संसाधनों की कमी है। कई क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा और बिजली की समस्या भी बनी रहती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा संसाधनों तक आसानी से पहुँच नहीं बना पाते। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की कमी तथा जागरूकता का अभाव भी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष निवेश एवं योजनाओं की आवश्यकता है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में समानता लाई जा सके।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature)- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के पश्चात अनेक शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं तथा नीति विश्लेषकों द्वारा इसके विभिन्न आयामों पर अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों में नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों, इसकी उपयोगिता, क्रियान्वयन की चुनौतियों तथा विशेष रूप से शैक्षिक अवसंरचना की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

1. शर्मा (2021) ने अपने अध्ययन में बताया कि नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक व्यावहारिक, कौशल-आधारित तथा विद्यार्थीकेंद्रित बनाने का प्रयास करती है। उनके अनुसार नीति में बहुविषयक शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षण तथा डिजिटल शिक्षा जैसे प्रावधान विद्यार्थियों के समग्र विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी संसाधनों और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी नीति के सफल क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है।
2. सिंह एवं यादव (2022) ने उच्च शिक्षण संस्थानों में नई शिक्षा नीति के प्रभाव का अध्ययन करते हुए पाया कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पर्याप्त प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय तथा डिजिटल सुविधाएँ उपलब्ध न होने के कारण नीति के कई प्रावधान व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो पा रहे हैं। उनके अनुसार शिक्षा के डिजिटलीकरण हेतु मजबूत तकनीकी अवसंरचना आवश्यक है।

3. कुमार (2021) के अध्ययन में यह उल्लेख किया गया कि नई शिक्षा नीति में कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, किंतु अधिकांश विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु आवश्यक उपकरण, प्रशिक्षक तथा संसाधनों का अभाव है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को शिक्षा क्षेत्र में अधिक वित्तीय निवेश करना चाहिए।
4. मिश्रा एवं तिवारी (2023) ने ग्रामीण और शहरी विद्यालयों की तुलना करते हुए निष्कर्ष निकाला कि शहरी क्षेत्रों में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट, स्मार्ट क्लास तथा डिजिटल उपकरणों की कमी के कारण विद्यार्थी नई शिक्षण पद्धतियों का पूर्ण लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
5. वर्मा (2022) ने शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों, डिजिटल उपकरणों तथा बहुविषयक शिक्षण पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। बिना प्रशिक्षित शिक्षकों के नीति का प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं है।

उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है, किंतु अवसंरचना की कमी, तकनीकी संसाधनों का अभाव, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी तथा वित्तीय समस्याएँ इसके सफल क्रियान्वयन में प्रमुख बाधाएँ हैं। इसलिए नीति की सफलता सुनिश्चित करने हेतु शैक्षिक अवसंरचना के विकास तथा संसाधनों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

विवेचना (Discussion)- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य शिक्षा को केवल परीक्षा एवं डिग्री प्राप्ति तक सीमित न रखकर विद्यार्थियों के समग्र विकास, कौशल निर्माण तथा व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ना है। प्रस्तुत अध्ययन एवं पूर्ववर्ती शोधों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि नई शिक्षा नीति के सिद्धांत अत्यंत प्रगतिशील एवं समयानुकूल हैं, किंतु इनके सफल क्रियान्वयन में अवसंरचना की कमी एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आती है। **शर्मा (2021)** के अध्ययन में यह उल्लेख किया गया कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देती है, जिसमें रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन तथा कौशल विकास पर बल दिया गया है। किंतु उनके शोध में यह भी स्पष्ट किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की आधारभूत स्थिति अत्यंत कमजोर है। कई विद्यालयों में पर्याप्त भवन, प्रयोगशालाएँ तथा पुस्तकालय उपलब्ध नहीं हैं। प्रस्तुत अध्ययन भी इस निष्कर्ष का समर्थन करता है कि यदि शैक्षिक संस्थानों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहेगा, तो नीति के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लागू करना कठिन होगा।

सिंह एवं यादव (2022) ने उच्च शिक्षण संस्थानों में डिजिटल शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करते हुए पाया कि नई शिक्षा नीति तकनीकी शिक्षा एवं ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देती है, लेकिन अधिकांश महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास, इंटरनेट तथा कंप्यूटर लैब की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कोविड-19 महामारी के दौरान यह समस्या और अधिक स्पष्ट हुई, जब अनेक विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह गए। प्रस्तुत शोध में भी यह तथ्य सामने आता है कि डिजिटल विभाजन (Digital Divide) नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में एक बड़ी बाधा है। विशेष रूप से ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी डिजिटल संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा में पीछे रह जाते हैं।

कुमार (2021) ने अपने अध्ययन में व्यावसायिक एवं कौशल-आधारित शिक्षा पर विशेष चर्चा की है। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर से ही कौशल विकास एवं रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किंतु अधिकांश विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु आवश्यक उपकरण, प्रयोगशालाएँ तथा प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। प्रस्तुत अध्ययन में भी यह स्पष्ट हुआ कि केवल पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर देने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव नहीं है, बल्कि उसके लिए आवश्यक संसाधनों का विकास भी अनिवार्य है।

मिश्रा एवं तिवारी (2023) ने ग्रामीण और शहरी विद्यालयों की तुलना करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि शहरी क्षेत्रों में नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी है, क्योंकि वहाँ तकनीकी संसाधन एवं प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध हैं। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट, बिजली तथा डिजिटल उपकरणों की कमी नीति की सफलता में बाधा उत्पन्न करती है। प्रस्तुत अध्ययन भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है कि शिक्षा में समानता स्थापित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष निवेश और योजनाओं की आवश्यकता है।

वर्मा (2022) ने शिक्षक प्रशिक्षण को नई शिक्षा नीति की सफलता का आधार माना है। उनके अनुसार आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए शिक्षकों का तकनीकी एवं व्यावसायिक रूप से दक्ष होना आवश्यक है। वर्तमान अध्ययन में भी यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आया कि अनेक शिक्षक नई शिक्षण तकनीकों एवं डिजिटल माध्यमों के उपयोग में पूर्णतः प्रशिक्षित नहीं हैं। इससे नई शिक्षा नीति के प्रावधान व्यवहारिक रूप से सीमित हो जाते हैं। इसलिए नियमित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा कार्यशालाओं का आयोजन आवश्यक है।
उपरोक्त शोध अध्ययनों एवं वर्तमान विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। किंतु इसके सफल क्रियान्वयन के लिए मजबूत शैक्षिक अवसंरचना, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता, प्रशिक्षित शिक्षक तथा पर्याप्त वित्तीय निवेश अत्यंत आवश्यक हैं। यदि सरकार, शिक्षण संस्थान एवं समाज मिलकर इन समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य करें, तो नई शिक्षा नीति भारत को ज्ञान-आधारित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

निष्कर्ष- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, समावेशी, कौशल-आधारित तथा रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी पहल है। इस नीति के माध्यम से शिक्षा को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रखकर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन तथा व्यावहारिक दक्षताओं से जोड़ने का प्रयास किया गया है। 5+3+3+4 शिक्षा संरचना, मातृभाषा में शिक्षण, डिजिटल शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन तथा व्यावसायिक शिक्षा जैसे प्रावधान भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

हालाँकि, प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में अवसंरचना की कमी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। देश के अनेक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पर्याप्त भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, स्मार्ट क्लास, इंटरनेट सुविधा तथा प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव देखा जाता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक संसाधनों की कमी के कारण नीति के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करना कठिन प्रतीत होता है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के बावजूद तकनीकी असमानता और आर्थिक विषमता भी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल नई नीतियों का निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके सफल क्रियान्वयन हेतु मजबूत शैक्षिक अवसंरचना, प्रशिक्षित शिक्षक, पर्याप्त वित्तीय निवेश तथा तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता भी अनिवार्य है। यदि सरकार, शिक्षण संस्थान तथा समाज संयुक्त रूप से शिक्षा के आधारभूत ढाँचे को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य करें, तो नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इससे भारत की शिक्षा व्यवस्था अधिक गुणवत्तापूर्ण, व्यावहारिक तथा आत्मनिर्भर बन सकेगी और राष्ट्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

संदर्भ सूची -

1. शर्मा, आर. (2021). ग्रामीण भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ. जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट, 12(3), 45-52।
2. सिंह, ए., एवं यादव, पी. (2022). नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत डिजिटल अवसंरचना और उच्च शिक्षा. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, 8(2), 66-74।
3. कुमार, एस. (2021). नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल आधारित शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण. इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड सोसाइटी, 15(1), 28-36।
4. मिश्रा, वी., एवं तिवारी, एन. (2023). भारत में ग्रामीण एवं शहरी शैक्षिक अवसंरचना का तुलनात्मक अध्ययन. जर्नल ऑफ कंटेम्पररी एजुकेशन, 10(4), 81-90।
5. वर्मा, पी. (2022). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण एवं शैक्षिक सुधार. इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग, 6(2), 55-63।
6. भारत सरकार। (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
7. शिक्षा मंत्रालय। (2021). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की रणनीतियाँ. भारत सरकार।